



GURU DEEKSHAA IAS

CURRENT AFFAIRS GURU



Daily Current Affairs

1 August 2022

INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

1st August 2022

1. - राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान की रोकथाम के बारे में:	3
(i) अधिनियम के संबंध में:	3
(ii) अधिनियम के अन्य विवरण:	3
2. - अंतरिक्ष मलबे का विवरण:	4
(i) के बारे में:	4
(ii) अंतरिक्ष कबाड़ क्या जोखिम पैदा करता है?	4
(iii) अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है?	4
(iv) क्या किया जाए?	5
3. - भारत में विमानन क्षेत्र के बारे में:	6
(i) पार्श्वभूमि:	6
(ii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई):	6
(iii) 2016 के लिए राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति:	6
(iv) नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुधार:	6
(v) नागरिक उड्डयन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों के विवरण में अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं:	7
4. - काउंट्रि पोर्टल का विवरण:	8

संपादकीय विश्लेषण 9

1. चुनावी बांड: 9

(i) चुनावी बांड कैसे काम करते हैं? 9

(ii) चुनावी बांड की आलोचना क्यों की जा रही है? 9

(iii) कैसे आगे बढ़ा जाए: 10

2. भारत भूटान संबंध: 11

(i) ऐतिहासिक संबंध: 11

(ii) भारत के लिए भूटान का महत्व: 11

(iii) सहयोग क्षेत्र: 12

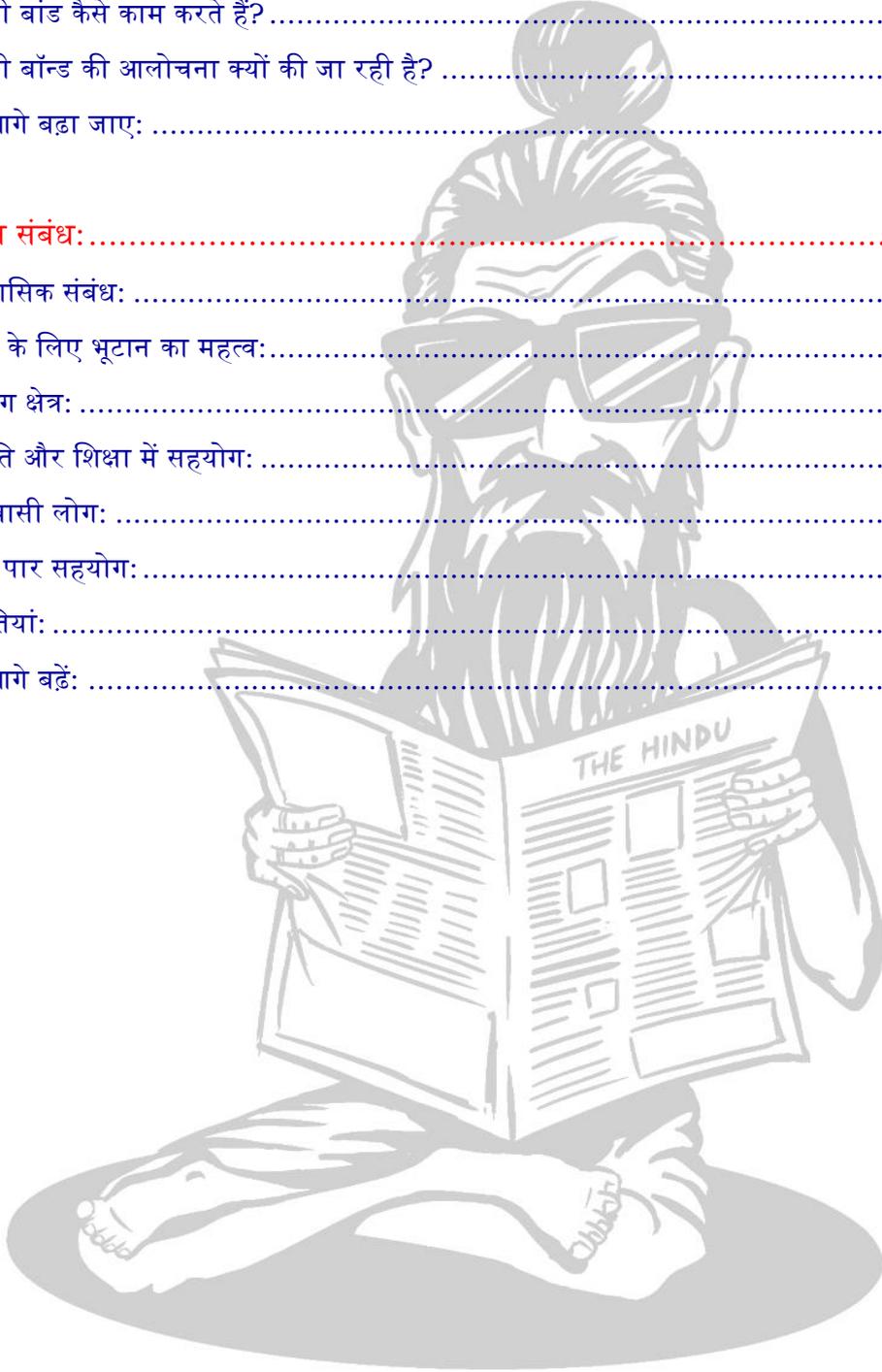
(iv) संस्कृति और शिक्षा में सहयोग: 12

(v) आदिवासी लोग: 13

(vi) सीमा पार सहयोग: 13

(vii) चुनौतियां: 13

(viii) कैसे आगे बढ़ें: 13



1. - राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान की

रोकथाम के बारे में:

GS II

विषय→सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

➤ संदर्भ:

- भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस साल 2 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगे को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर के रूप में अपनाने के लिए कहा। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव को "सार्वजनिक आंदोलन" कहा।

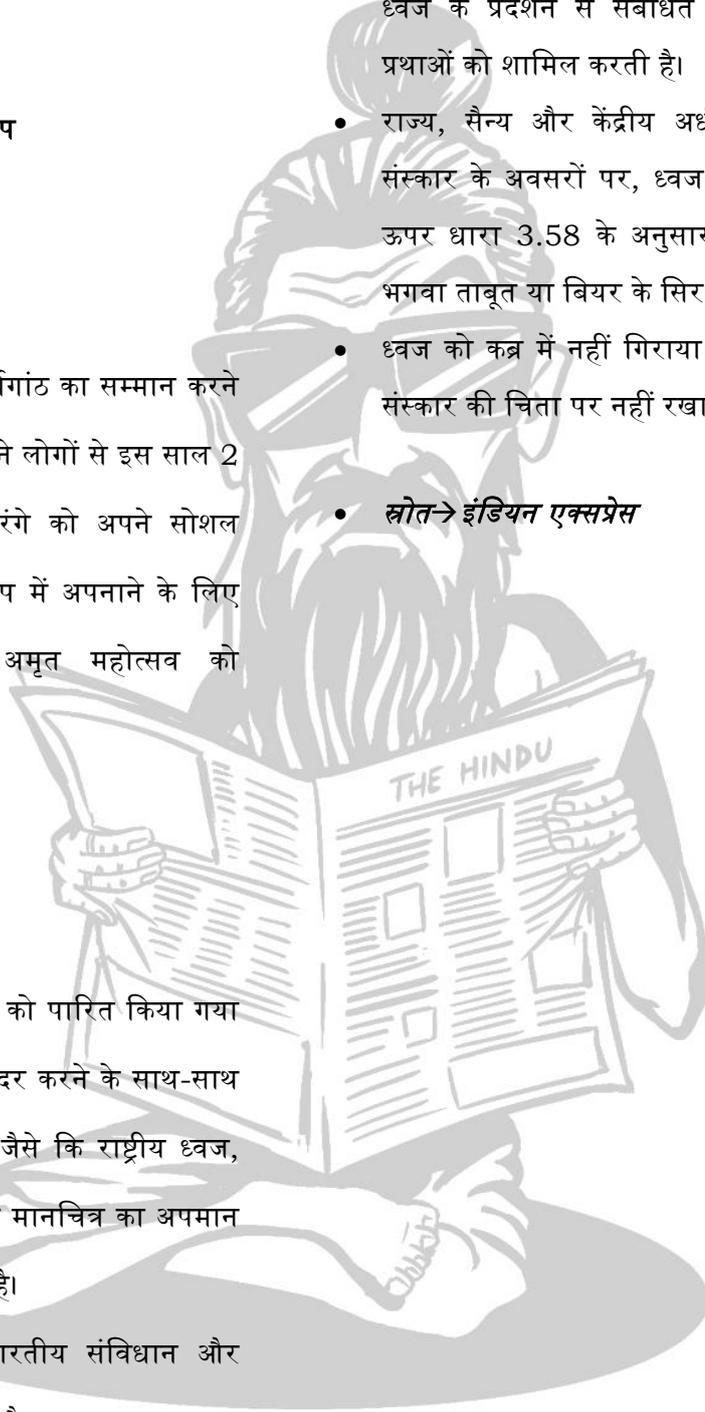
अधिनियम के संबंध में:

- कानून, जो 23 दिसंबर, 1971 को पारित किया गया था, भारत के संविधान का अनादर करने के साथ-साथ भारत के अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र का अपमान या अपमान करने से मना करता है।
- अधिनियम की धारा 2 में भारतीय संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान शामिल है।

अधिनियम के अन्य विवरण:

- भारतीय ध्वज संहिता, 2002, धारा 3.22, राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित नियमों, परंपराओं और प्रथाओं को शामिल करती है।
- राज्य, सैन्य और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अंतिम संस्कार के अवसरों पर, ध्वज को ताबूत या बायर के ऊपर धारा 3.58 के अनुसार लपेटा जाएगा, जिसमें भगवा ताबूत या बायर के सिर की ओर होगा।
- ध्वज को कब्र में नहीं गिराया जा सकता है या अंतिम संस्कार की चिता पर नहीं रखा जा सकता है।

• स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस



2. - अंतरिक्ष मलबे का विवरण:

अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

जीएस II

विषय→अंतरिक्ष संबंधी मुद्दे

के बारे में:

- एक अंतरिक्ष यान जिसे छोड़ दिया गया है और अब चालू नहीं है उसे "अंतरिक्ष जंक" कहा जाता है और लंबे समय तक पृथ्वी की कक्षा में रहा है।

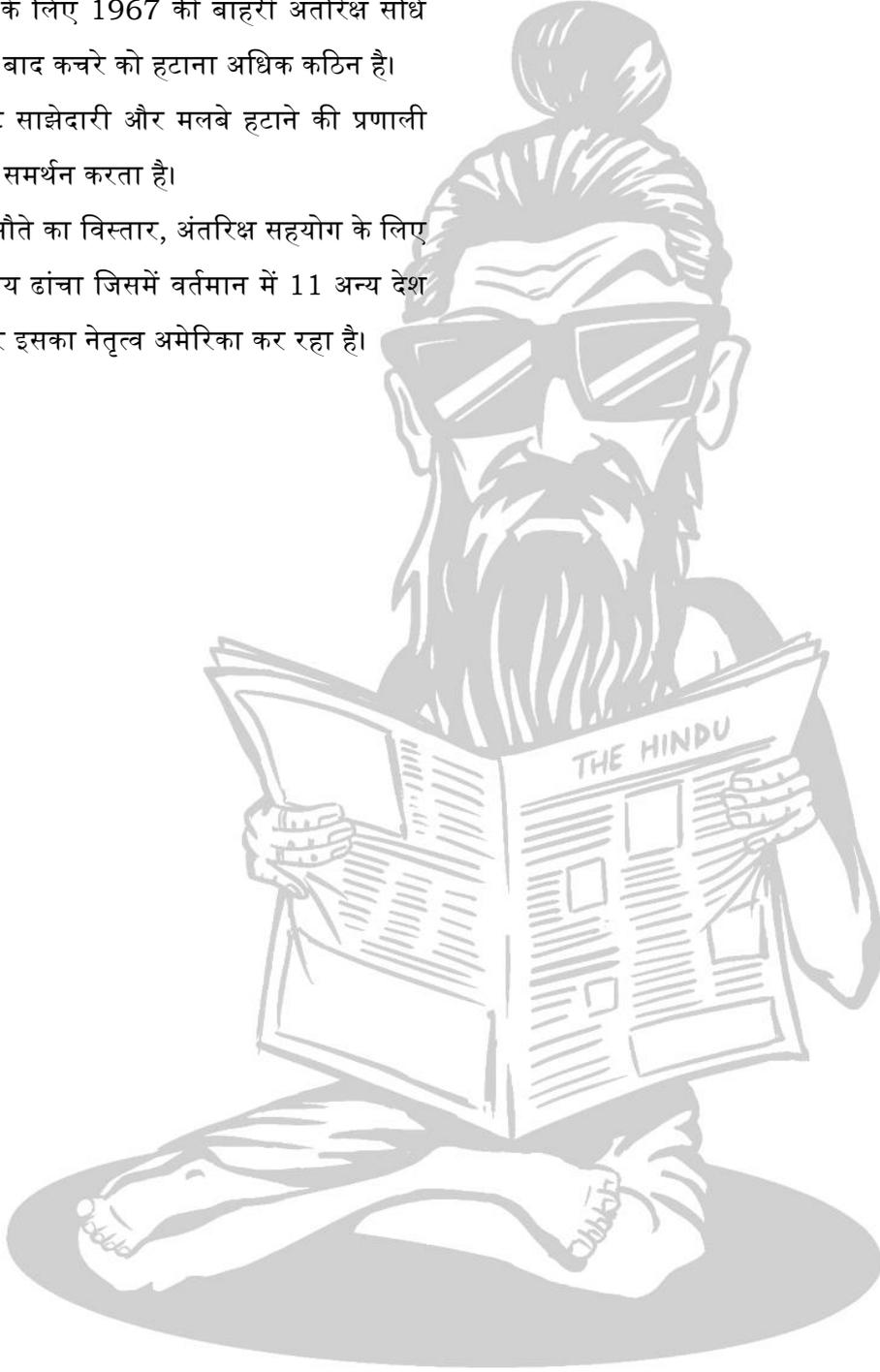
अंतरिक्ष कबाड़ क्या जोखिम पैदा करता है?

- समस्या तब और बढ़ जाती है जब अंतरिक्ष कबाड़ अन्य उपग्रहों या अन्य अंतरिक्ष मलबे से टकराता है।
- अंतरिक्ष कबाड़ का एक बेल्ट कुछ निम्न-पृथ्वी कक्षाओं को अनुपयोगी बना सकता है।
- विशेषज्ञों ने केसलर सिंड्रोम की चेतावनी दी है।
- अंतरिक्ष के मलबे से कक्षा में अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान होगा।
- अंतरिक्ष यान की बैटरी का विस्फोट और सिस्टम का रिसाव दोनों संभव हैं।
- अंतरिक्ष में मलबे (आईएसएस) से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को लगातार खतरा है।
- केसलर सिंड्रोम बताता है कि लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में वस्तुओं के बीच टकराव का डोमिनोज़ प्रभाव हो सकता है जिससे आगे टकराव की संभावना बढ़ जाती है।

- मलबे में कमी के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों का पहला सेट 1995 में नासा द्वारा कक्षीय मलबे कार्यक्रम कार्यालय के निर्माण के साथ जारी किया गया था।
- इसने सिफारिश की कि मिशन के समापन के 25 वर्षों के भीतर पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के लिए उपग्रहों का निर्माण किया जाए।
- यूरोपीय योजना ClearSpace-1, अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए पृथ्वी से पहला मिशन, 2025 में लॉन्च होगा।
- पड्यू विश्वविद्यालय के शोधकर्ता अंतरिक्ष को साफ करने के प्रयास में परीक्षण के लिए एक प्रोटोटाइप Spinnaker3 ड्रैग सेल को निम्न-पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च कर रहे हैं।
- जापानी स्टार्ट-अप एस्ट्रोस्केल ने एक उपग्रह लॉन्च किया है जो निष्क्रिय उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष जंक एकत्र करता है।
- इसरो ने अगस्त 2020 में उपग्रहों को अंतरिक्ष के मलबे और अंतरिक्ष के अन्य खतरों से बचाने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में NETRA परियोजना शुरू की।
- यदि कोई उपग्रह खराब होना शुरू करता है, तो उसे विचलित होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के अनुसार, वायुमंडल में इसके पुनः प्रवेश के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए।

क्या किया जाए?

- सरकार को उनके अंतरिक्ष यान पर स्थायी संपत्ति का अधिकार देने के लिए 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि में संशोधन के बाद कचरे को हटाना अधिक कठिन है।
- नासा कॉर्पोरेट साझेदारी और मलबे हटाने की प्रणाली के विकास का समर्थन करता है।
- आर्टेमिस समझौते का विस्तार, अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा जिसमें वर्तमान में 11 अन्य देश शामिल हैं और इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है।
- स्रोत → हिन्दू



3. - भारत में विमानन क्षेत्र के बारे में:

जीएस II

विषय→सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

पार्श्वभूमि:

- भारत में, जो 2020 तक दुनिया भर में नागरिक उड्डयन के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा, यमुना नदी के पार नैनी के लिए मेल ले जाने वाली पहली वाणिज्यिक उड़ान ने 1911 में इलाहाबाद के पोलो फील्ड से उड़ान भरी थी।
- एयर इंडिया वर्तमान में देश का ध्वजवाहक है और 2011 में भारतीय के साथ विलय के बाद भारत को शेष विश्व से जोड़ने के लिए आवश्यक है।
- भारत 2024 तक दुनिया के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तीसरे सबसे बड़े स्थान पर होगा। 2016 में इसके हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने वाले 131 मिलियन लोगों में से 100 मिलियन घरेलू यात्री थे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई):

- एएआई ने 1995 में व्यवसाय करना शुरू किया। हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का निर्माण, अद्यतन, प्रबंधन और रखरखाव इस मिनी-रत्न कंपनी द्वारा किया जाता है।
- GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, या GAGAN के रूप में जानी जाने वाली तकनीक, GPS सिग्नल की सटीकता और निर्भरता को बढ़ाती है। यह एएआई और इसरो के सहयोग से किया जाता है।

- सरकार ने अनुसूचित और अनिर्धारित हवाई परिवहन सेवाओं के लिए एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी है।
- फुरसतगंज, रायबरेली (यूपी) में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) की स्थापना।
- RGNAU, या राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, रायबरेली (यूपी) में स्थित है।

2016 के लिए राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति:

- आजादी के बाद यह पहली नीति है।
- इसका उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा, जो बदले में पर्यटन को आकर्षित करेगा, रोजगार बढ़ाएगा और क्षेत्रीय विकास की संतुलित दर का उत्पादन करेगा।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुधार:

- शीर्ष पायदान की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की स्थापना करके, सरकार ने देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। उसमें समाविष्ट हैं:
 - एएआई ने लगभग रुपये खर्च करने के लिए एक विकास कार्यक्रम शुरू किया है। विमानन उद्योग में प्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने के लिए नए टर्मिनल निर्माण, टर्मिनल विस्तार और संशोधन, रनवे विस्तार या मजबूती, एप्रन, एयरपोर्ट नेविगेशन सर्विसेज (एएनएस), कंट्रोल टावर, तकनीकी ब्लॉक आदि पर अगले 4-5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपये।

- भारत सरकार ने "सैद्धांतिक रूप से" देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों (भारत सरकार) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। छह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, जिनमें शिरडी, महाराष्ट्र शामिल हैं; दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल; पाक्योंग, सिक्किम; कन्नूर, केरल; ओरवकल, आंध्र प्रदेश; और कलबुर्गी, कर्नाटक को अब तक चालू कर दिया गया है।
- पीपीपी का उपयोग नए और मौजूदा दोनों हवाई अड्डों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
- क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत 359 मार्ग - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान), जिसमें 2 वाटर एयरोड्रोम और 5 हेलीपोर्ट शामिल हैं, ने 27 जुलाई, 2021 तक 59 अनारक्षित / कम सेवा वाले हवाई अड्डों को जोड़ना शुरू कर दिया है।
- कुशल हवाई क्षेत्र प्रबंधन, छोटे उड़ान पथ और कम ईंधन की खपत के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर विमान पथ को अनुकूलित करने के लिए भारतीय वायु सेना के साथ सहयोग
- एयर बबल अरेंजमेंट्स के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे कैरियर के साथ उचित और समान व्यवहार किया जाए।
- सरकार ने कई तरह की नीतिगत पहलों के साथ एयरलाइनों को सहायता प्रदान की है, जैसे कि कर में कटौती, विमान के लिए लाभप्रद पट्टे और वित्तपोषण की स्थिति का निर्माण, द्विपक्षीय यातायात अधिकारों का प्रभावी उपयोग, और हवाई नेविगेशन सुविधाओं के उन्नयन, ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिल सके।
- सरकार द्वारा एयरलाइंस पर आधुनिक वाइड-बॉडी विमान खरीदने का दबाव डाला गया है। विस्तार एयरलाइंस द्वारा दो नए वाइड-बॉडी विमान पहले ही अधिग्रहित किए जा चुके हैं।

- COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप एयरलाइंस, हवाई अड्डों और संबंधित सेवाओं सहित विमानन क्षेत्र आर्थिक रूप से तनावग्रस्त हो गया है।

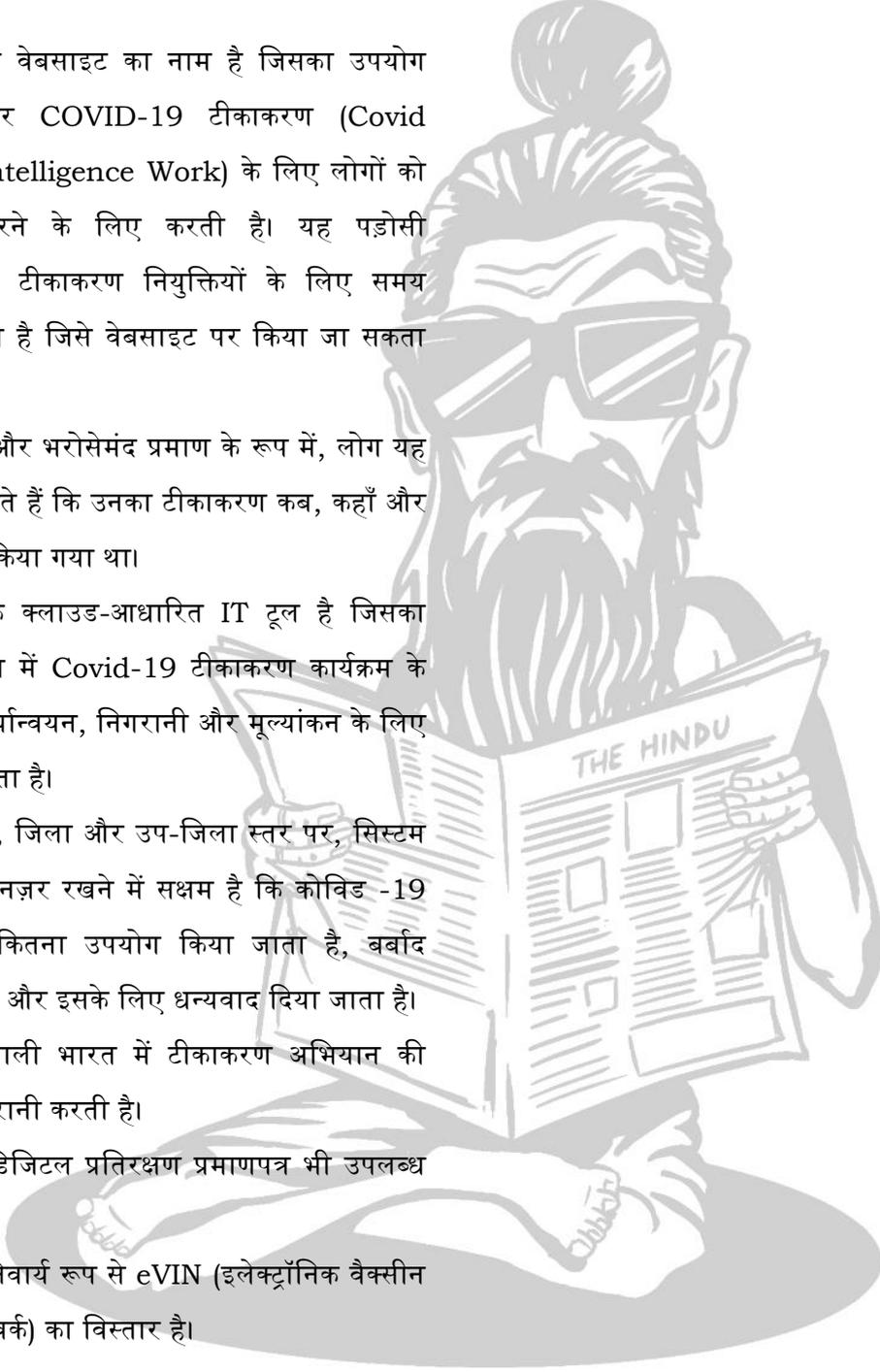
नागरिक उड्डयन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों के विवरण में अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं:

- हवाई अड्डों के लिए बुनियादी ढांचा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और निजी ऑपरेटरों द्वारा प्रदान किया जाता है।
- नए और पुराने दोनों हवाई अड्डों में पीपीपी के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देना
- हवाई नेविगेशन प्रणाली की प्रभावशीलता की जाँच करें।
- एयर बबल अरेंजमेंट्स के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे कैरियर के साथ उचित और समान व्यवहार किया जाए।
- घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवाओं के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई।
- विमान पट्टे पर देने और वित्तपोषण के लिए वातावरण अनुकूल है।
- कुशल हवाई क्षेत्र प्रबंधन, छोटे उड़ान पथ और कम ईंधन उपयोग के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर विमान मार्गों को अनुकूलित करने के लिए भारतीय वायु सेना के साथ साझेदारी।
- उत्तर खोजने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर काम करना।
- स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस

4. - काउइन पोर्टल का विवरण:

प्रीलिम्स विशिष्ट विषय

- CoWIN उस वेबसाइट का नाम है जिसका उपयोग भारत सरकार COVID-19 टीकाकरण (Covid Vaccine Intelligence Work) के लिए लोगों को नामांकित करने के लिए करती है। यह पड़ोसी COVID-19 टीकाकरण नियुक्तियों के लिए समय प्रदर्शित करता है जिसे वेबसाइट पर किया जा सकता है।
- एक सुरक्षित और भरोसेमंद प्रमाण के रूप में, लोग यह पता लगा सकते हैं कि उनका टीकाकरण कब, कहाँ और किसके द्वारा किया गया था।
- CoWIN एक क्लाउड-आधारित IT टूल है जिसका उपयोग भारत में Covid-19 टीकाकरण कार्यक्रम के आयोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर, सिस्टम इस बात पर नज़र रखने में सक्षम है कि कोविड -19 वैक्सीन का कितना उपयोग किया जाता है, बर्बाद किया जाता है और इसके लिए धन्यवाद दिया जाता है।
- CoWIN प्रणाली भारत में टीकाकरण अभियान की लगातार निगरानी करती है।
- इंटरनेट पर डिजिटल प्रतिरक्षण प्रमाणपत्र भी उपलब्ध हैं।
- CoWIN अनिवार्य रूप से eVIN (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) का विस्तार है।
- स्रोत→ हिन्दू



संपादकीय विश्लेषण

चुनावी बाँड की आलोचना क्यों की जा रही है?

1. चुनावी बांड:

चुनावी बांड कैसे काम करते हैं?

- इन बांडों की कोई अधिकतम खरीद राशि नहीं है और इन्हें 1,000, 10,000, एक लाख, दस लाख और एक करोड़ रुपये के गुणकों में खरीदा जा सकता है।
- ये बांड केवल भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी और भुनाए जा सकते हैं, और उनकी समाप्ति तिथि पंद्रह दिन है।
- इन बांडों को केवल एक पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते से ही भुनाया जा सकता है।
- कोई भी भारतीय नागरिक जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के प्रत्येक महीने में कुल दस दिनों के लिए बांड प्राप्त कर सकता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है।
- एक व्यक्ति स्वयं या समूह में अन्य लोगों के साथ बांड खरीद सकता है।
- बांड में दाता के नाम का उल्लेख नहीं है।
- राजनीतिक दल दानदाताओं को अपने पैसों जैसी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए नहीं कहते हैं यदि वे चुनावी बांड खरीदते हैं या रुपये से कम का दान करते हैं। 20,000
- चुनावी बांड कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।
- एक "कैशलेस-डिजिटल अर्थव्यवस्था" में संक्रमण के दौर से गुजर रहे देश में, सरकार ने प्रस्ताव को "चुनावी सुधार" के रूप में संदर्भित किया।

- इसकी केंद्रीय अवधारणा को धता बताते हुए: इलेक्टोरल बाँड योजना को इसकी अधिकांश आलोचना इस बात के लिए मिली है कि इसे जो करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, उसके ठीक विपरीत को पूरा करने के लिए, जो कि चुनावी खर्च को पारदर्शी बनाने के लिए था।
- उदाहरण के लिए, कुछ का दावा है कि चुनावी बांड की गुमनामी केवल आम जनता और प्रतिस्पर्धी दलों पर लागू होती है।
- **जबरन वसूली की संभावना** : इस तथ्य के कारण कि ये बांड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक (एसबीआई) के माध्यम से बेचे जाते हैं, सरकार के पास अपने प्रतिद्वंद्वियों के फंडर्स के बारे में जानकारी होती है।
- नतीजतन, वर्तमान प्रशासन के पास सत्ताधारी पार्टी को देने या पैसे की मांग करने से इनकार करने के लिए व्यवसायों को दंडित करने की शक्ति है, विशेष रूप से बड़े उद्यमों से, बाद वाले को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए।
- **लोकतंत्र के खिलाफ एक हड़ताल**: 2017 के वित्त अधिनियम में संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त चंदे का खुलासा करने से छूट दी है।
- इससे पता चलता है कि मतदाताओं को यह नहीं बताया जाएगा कि कौन, क्या, या किस पार्टी को कितना दे रहा है।
- एक प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र में, मतदाता उन लोगों को चुनते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।

- **जानने का अधिकार समझौता है:** भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से तर्क दिया है कि "जानने का अधिकार" भारतीय संविधान (अनुच्छेद 19) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, खासकर चुनावों के संदर्भ में।
- जो लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ हैं, हालांकि चुनावी बांड आम जनता को कोई जानकारी नहीं देते हैं।
- वर्तमान प्रशासन उपरोक्त गुमनामी से मुक्त है क्योंकि यह हमेशा भारतीय स्टेट बैंक से दाता जानकारी (एसबीआई) प्राप्त करने के लिए डेटा मांग सकता है।
- इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान प्रशासन निष्पक्ष चुनाव को विफल करने के लिए इस जानकारी का फायदा उठा सकता है।
- चुनावी बांड कार्यक्रम, जो राजनीतिक चंदे पर सभी पूर्व बाधाओं को दूर करता है और अनिवार्य रूप से धनी कंपनियों को अभियानों का भुगतान करने की अनुमति देता है, वही है जो क्रोनी पूंजीवाद को व्यवहार्य बनाता है।
- एक "क्रोनी कैपिटलिज्म" आर्थिक प्रणाली राजनीतिक और वाणिज्यिक अभिजात वर्ग के बीच घनिष्ठ, पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की विशेषता है।
- संपूर्ण सरकारी प्रणाली में जवाबदेही और खुलेपन को बढ़ावा देने के लिए अब मौजूद कानूनी अंतराल को बंद करना महत्वपूर्ण है।
- मतदाता जागरूकता पहल का समर्थन करके भी बदलाव ला सकते हैं जिससे पर्याप्त प्रगति हो सके। अत्यधिक खर्च या रिश्वतखोरी में लिप्त राजनेताओं और पार्टियों को खारिज करने वाले मतदाता लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे।

कैसे आगे बढ़ा जाए:

- भ्रष्टाचार के कभी न खत्म होने वाले चक्र और लोकतांत्रिक राजनीति के क्षरण को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों के अलावा, राजनीतिक धन उगाहने पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है।

2. भारत भूटान संबंध:

ऐतिहासिक संबंध:

- 1910 में भूटान को ब्रिटिश भारत का संरक्षक बनाया गया था, तब से भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं, जिससे अंग्रेजों को अपनी राजनयिक और रक्षा नीतियों का "मार्गदर्शन" करने की अनुमति मिली।
- 1947 में भारत की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले राष्ट्रों में से एक भूटान था। तब से, देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ है, खासकर चीन के साथ भूटान के अपने अशांत इतिहास के आलोक में।
- भूटान और भारत के बीच 699 किलोमीटर की सीमा के साथ-साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं। बौद्ध संत, गुरु पद्मसंभव का बौद्ध धर्म के प्रसार और दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के निर्माण पर बहुत प्रभाव था।
- 1968 में, भारत के नेतृत्व में, भूटान ने थिम्पू में एक विशेष प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना की। दो विशेष प्रतिनिधि कार्यालयों को 1978 में एक उन्नयन प्राप्त हुआ और उन्हें राजनयिक दर्जा दिया गया।
- भूटान और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों की नींव 1949 की शांति और मित्रता की भारत-भूटान संधि द्वारा निर्धारित की गई थी। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समझौते का अनुच्छेद 2 भारत को भूटान की विदेश नीति पर शक्ति प्रदान करता है। नतीजतन, 2007 में समझौते में कई बदलाव हुए।
- नया समझौता भूटान को तब तक हथियार खरीदने की अनुमति देता है जब तक कि भारतीय हितों की रक्षा की

जाती है और सरकार या निजी व्यक्तियों द्वारा फिर से कोई हथियार निर्यात नहीं किया जाता है।

- वर्तमान संधि के अनुच्छेद 6 और 7 दोनों देशों के नागरिकों के लिए "राष्ट्रीय उपचार" और समान अधिकारों पर चर्चा करते हैं।

भारत के लिए भूटान का महत्व:

भौगोलिक महत्व:

- भूटान की सीमा से लगे चार भारतीय राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं।
- चीन और भारत के बीच, हिमालयी राष्ट्र भूटान एक पड़ाव के रूप में कार्य करता है।
- भारत के लिए भूटान की वर्तमान सीमाओं, विशेषकर उसकी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा आवश्यक है।

वित्तीय महत्व:

- भूटान एक ऐसा देश है जहां भारतीय पूंजी का निवेश किया जाता है और जहां भारतीय वस्तुओं की बिक्री होती है।
- भारत की भूटान से प्रचुर मात्रा में जल विद्युत तक पहुंच भी है।

राजनीतिक महत्व:

- भूटान की राजनीतिक स्थिरता को भारत महत्व देता है। चरमपंथी संगठन और भारत विरोधी गतिविधियां भूटान की अशांति और अस्थिरता में शरण पा सकती हैं।

सहयोग क्षेत्र:

व्यापार:

- दोनों देशों के बीच व्यापार 1972 के भारत-भूटान व्यापार और पारगमन समझौते द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे हाल ही में नवंबर 2016 में नवीनीकृत किया गया था।
- समझौता भूटान से अन्य देशों में माल के शुल्क मुक्त पारगमन की अनुमति देता है और दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करता है।
- भारत भूटान का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। 2018 के जनवरी से जून तक, दोनों देशों का संयुक्त वाणिज्य रुपये का था। 4318.59 करोड़।
- भूटान के बिजली, फेरोसिलिकॉन, पोर्टलैंड सीमेंट और अन्य चीजों के प्राथमिक आयात के विपरीत, भूटान को भारत का मुख्य निर्यात खनिज उत्पाद, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, बिजली के उपकरण और अन्य सामान हैं।

आर्थिक सहायता:

- भारत भूटान का प्रमुख विकास भागीदार है। 1961 में भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना को अपनाए जाने के बाद से, भारत अपने FYPs को वित्तीय रूप से समर्थन दे रहा है। भारत ने रु. भूटान की 12वीं FYP की ओर 4500 करोड़।

जलभृत में संसाधन:

- भारत जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। यह न केवल घरेलू उपयोग के

लिए बिजली प्रदान करता है, बल्कि भारत को अतिरिक्त बिजली बेचकर पैसा भी कमाता है।

- भारत सरकार ने अब तक भूटान में तीन जलविद्युत परियोजनाओं (HEPs) का निर्माण किया है। भारत अब भूटान को मंगदेछु नदी पर बिजली संयंत्र बनाने में मदद कर रहा है।
- जलविद्युत सहयोग पर 2006 का समझौता इस जलविद्युत सहयोग को नियंत्रित करता है। इस समझौते के एक प्रोटोकॉल के अनुसार, भारत ने वर्ष 2020 तक भूटान को न्यूनतम 10,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन में मदद करने और इस विकास से किसी भी अतिरिक्त बिजली का आयात करने का वादा किया है।
- बाढ़ से निपटने के लिए, भारत और भूटान ने विशेषज्ञों के एक संयुक्त समूह (JGE) की भी स्थापना की।

सीमा सुरक्षा:

- दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के लिए सचिव स्तर पर एक तंत्र है।
- सीमा प्रबंधन और अन्य प्रासंगिक विषयों (आरजीओबी) पर समन्वय की सुविधा के लिए सीमावर्ती राज्यों और भूटान की शाही सरकार के बीच एक सीमा जिला समन्वय बैठक (बीडीसीएम) तंत्र भी है।

संस्कृति और शिक्षा में सहयोग:

- कई भूटानी किशोर जो कॉलेज जाने की योजना बना रहे हैं, भारत में अपनी शिक्षा जारी रखते हैं। भूटान के छात्रों के लिए भारत सरकार की ओर से अनेक छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं।

- दोनों देश अक्सर सांस्कृतिक विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना 2003 में अंतरसांस्कृतिक संचार को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी।

आदिवासी लोग:

- भूटान में लगभग 60,000 भारतीय नागरिक निवास करते हैं, उनमें से अधिकांश सड़कों और पनबिजली स्टेशनों के निर्माण में कार्यरत हैं।
- इसके अतिरिक्त, भूटान से 8000-10,000 दिहाड़ी मजदूर सीमावर्ती कस्बों में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं।

सीमा पार सहयोग:

- भारत और भूटान ने मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) बनाया, जो एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से संबंधित है।
- इसके अतिरिक्त, वे दोनों विभिन्न बहुपक्षीय मंचों जैसे बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल), बिम्स्टेक (बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) आदि में भाग लेते हैं।

चुनौतियां:

- भारत ने कभी-कभी भूटान में घरेलू मामलों में दखल दिया है। इस वजह से आज भूटान के लोगों की भारत के प्रति नकारात्मक राय है।

- चूंकि भारत को भूटान की अतिरिक्त बिजली से तुलनात्मक रूप से कम लागत पर लाभ होता है, इसलिए भूटान की यह धारणा बढ़ती जा रही है कि भारत व्यक्तिगत लाभ के लिए भूटान की जलविद्युत क्षमता का विकास कर रहा है।
- पवन, सौर और अन्य स्रोतों सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए भारत के प्रवास के कारण, भूटान अपनी जलविद्युत परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में चिंतित है।
- दक्षिण-पूर्वी भूटान के घने जंगलों में आतंकवादी शिविरों की अनधिकृत स्थापना ने दोनों देशों के लिए चिंता बढ़ा दी है।
- चुंबी घाटी और डोकलाम जैसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों पर चीन के चल रहे दावों के साथ-साथ भूटान के साथ घनिष्ठ राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने के उसके निरंतर प्रयासों ने भारत को लंबे समय से चिंतित किया है।

कैसे आगे बढ़ें:

- भारत को उन लाभों को उजागर करने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है जो इसकी पहल से भूटान को मिलते हैं।
- भारत को भूटान के साथ काम करने के नए अवसरों की तलाश लगातार करनी चाहिए। इसरो द्वारा भूटान में अपने ग्राउंड स्टेशन का पता लगाने का निर्णय एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है। यह स्टेशन भूटान को उसके बाहरी इलाकों में मौसम की जानकारी देकर उसकी मदद करेगा।
- भले ही यह एक संरक्षक के रूप में कार्य कर सकता है, भारत को भूटान के घरेलू मुद्दों से दूर रहने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

- चीन के साथ लगने वाली राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं दोनों देशों द्वारा साझा की जाती हैं। नतीजतन, इस मामले को हल करने के लिए, दोनों पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों को रोका जाना चाहिए।
- दोनों देशों को हमेशा एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे पड़ोसी हैं। इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से लगातार उच्च स्तरीय यात्राओं की आवश्यकता है।





GURU DEEKSHAA IAS

For Daily Current affairs classes,
important UPSC notes in English & Kannada,
Subscribe & follow our official channels



Guru Deekshaa IAS



t.me/Guru_DEEKSHAAIAS



Watch Daily Current Affairs

NEWSPOT

@ 08pm